

हर कौशल विकास केंद्र का 3 माह में एक बार करें निरीक्षण

उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने अधिकारियों को दिए आदेश

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। हमीरपुर

उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने जिला रोजगार अधिकारी तथा कौशल विकास योजना के तहत गठित जिला स्तरीय समिति के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह तीन महीने में एक बार प्रत्येक

जिले के 19 हजार 343 लाभार्थियों को दिए 18 करोड़ 31 लाख रुपये

कौशल विकास केंद्र का औचक निरीक्षण करें। वे सोमवार को कौशल विकास भत्ता के अंतर्गत जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। उन्होंने कहा कि जिला में कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत 30 जून तक 19 हजार 343 लाभार्थियों को 18 करोड़ 31 लाख रुपये की राशि कौशल विकास भत्ता के रूप में उपलब्ध कराई गई है। डीसी ने कहा कि अधिकारी योजना के अंतर्गत जिला में संचालित किए जा रहे समस्त सरकारी तथा गैर सरकारी केंद्रों की



कौशल विकास भत्ता योजना के तहत जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करती उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा।

भोरंज ब्लॉक में दो केंद्रों को संचालित करने के आदेश

संचालित करने की अनुमति प्रदान की। साथ ही इन केंद्रों में प्रशिक्षण ले रहे लाभार्थियों को अप्रैल से कौशल विकास भत्ता देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

नियमित चेकिंग करें तथा यदि कोई कमी पाई जाती है तो केंद्र संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करें।

डीसी ने भोरंज विकास खंड के अंतर्गत शिफ्ट किए गए दो कौशल विकास केंद्रों को एक मुश्किल छूट देते हुए उपमंडल स्तरीय समिति की शिफ्टिंग पर उन्हें संचालित करने की अनुमति प्रदान की। साथ ही इन केंद्रों में प्रशिक्षण ले रहे लाभार्थियों को अप्रैल से कौशल विकास भत्ता देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त जिला कमेटी द्वारा जिले में कौशल विकास योजना के तहत बंद पड़े 6 कौशल विकास केंद्रों

में कौशल विकास भत्ता को हटकर उन्हें बंद करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त रत्न गौतम, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र विजय चौधरी, जिला रोजगार अधिकारी योग राज धीमान के अलावा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र हमीरपुर व बहुकर्मचारी संस्थान बड़ू के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

कर्मचारी आयोग ले टी-मेट की परीक्षा

नादौन। प्रदेश सरकार विद्युत विभाग में टी-मेट की भर्ती करने जा रही है, जिसमें दसवीं की मेरिट को भर्ती का मुख्य आधार बनाया गया है। भर्ती प्रक्रिया पर असंतोष जताते हुए इलेक्ट्रीशियन आईटीआई डिप्लोमा होल्डर प्रविंद कुमार, रजनीश, रजनीकांत, रवि, अनीश, रोहित, प्रिंस, कुश, मनोष, राहुल आदि ने बताया कि ऐसे में दसवीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही नौकरी मिलने की संभावना है, जबकि ऐसे आईटीआई होल्डर जिनकी आईटीआई में तो अच्छे रैंकिंग है लेकिन 10वीं में ज्यादा नंबर नहीं है, उनके लिए नौकरी पाने की संभावना काफी कम हो जाएगी। युवाओं ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि विद्युत विभाग में टी-मेट की परीक्षा को प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से करवाया जाए, ताकि सभी के लिए नौकरी के समान अवसर प्राप्त हों। उक्त युवाओं ने बताया कि भारतीय रेलवे में भी ग्रुप-डी के पदों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर करवाई जा रही है और टी-मेट भर्ती भी ग्रुप-डी में ही आती है। अतः रेलवे विभाग की तर्ज पर विद्युत विभाग भी लिखित परीक्षा आयोजित कर भर्ती करें। युवाओं ने चेतावनी कि अगर प्रदेश की भाजपा सरकार ने उनकी मांग को नजरअंदाज किया तो वे इस मामले को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

सांसद मोबाइल स्वास्थ्य कैंप में 500 का किया चेकअप

विधायक कमलेश ने सांसद के प्रयासों को सराहा



हिमाचल दस्तक। भोरंज

सोमवार को धर्मरोल में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य मेडिकल सेवा के तहत लगाए गए मेडिकल कैंप में गांव उखलमहा के सुदू राम ने 11000वें मरीज के रूप में अपना चेकअप करवाया। सुदू राम को विधायक कमलेश

कुमारी ने सम्मानित भी किया। इस कैंप में 500 रोगियों का चेकअप किया गया। उन्हें निशुल्क टेस्ट तथा दवाइयां भी वितरित की गईं। जानकारी के मुताबिक सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत दो महीने में साढ़े 11 हजार रोगियों का निशुल्क चेकअप किया जा चुका है। विधायक कमलेश कुमारी ने कहा कि सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा अपने आप में एक सराहनीय कदम है। उन्होंने बताया कि इस स्वास्थ्य सेवा के तहत चार विधानसभा क्षेत्रों भोरंज, धर्मपुर, सुजानपुर तथा झंडूता की 160 पंचायतों में कैंप आयोजित

किए जा चुके हैं। भोरंज की 44 पंचायतों में 3308 रोगियों का चेकअप किया गया है, जबकि धर्मपुर की 31 पंचायतों में 2231, झंडूता की 46 पंचायतों में 2570, सुजानपुर की 46 पंचायतों में 3393 रोगियों की जांच की गई है। अब तक 11502 लोगों का निशुल्क चेकअप किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि यह सुविधा भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर अवाहदेवी से शुरु हुई थी। विधायक ने सेवा को भोरंज विधानसभा क्षेत्र में आरंभ करने के लिए सांसद अनुराग लकुरा का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर प्रयास संस्था के सदस्य धर्मचंद वर्मा, योगेंद्र रावैर, कृष्ण चंद, विधि चंद, विजय कुमार, विपिन चिधरी वृजलाल भरवाल, मंडलाध्यक्ष जयमल ठकुर, महामंत्री अशोक, उपाध्यक्ष शशि शर्मा, महिला मोर्चा महामंत्री वीना कुमारी, पूर्व जिला परिषद सदस्य चुनी लाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

जाहू-भरेड़ी मार्ग का होगा कायाकल्प

प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत नाए सिरे से होगा निर्माण

हिमाचल दस्तक। भरेड़ी

जाहू से भरेड़ी वाया धर्मरोल सड़क का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रखरखाव होगा। नए सिरे से सड़क के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने 365 लाख की डीपीआर तैयार की है, जिसे राज्य से स्वीकृति मिलने के बाद केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेज दिया है। जाहू से भरेड़ी वाया भौर धर्मरोल सड़क हमीरपुर, सरकाघाट व अवाहदेवी को जोड़ती है। पुरानी

विभाग ने तैयार की 3.65 करोड़ रुपये की डीपीआर

सड़क होने व वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी होने की वजह से सड़क का पुनः निर्माण किया जाना जरूरी था।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सड़क के दोनों तरफ पानी की निकासी के लिए पक्की नालियों और पुलियों का निर्माण भी होगा। जगह-जगह साइन बोर्ड लगेंगे और

वाहनों को पास देने के लिए उचित स्थान होंगे। भोरंज उपमंडल में अकेली सड़क होगी, जिसका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण किया जाएगा। धर्मरोल पंचायत प्रधान विजय कुमार, भलवाणी पंचायत प्रधान संजीव अंगारिया, लुदर पंचायत प्रधान सुरेंद्र शर्मा, जाहू पंचायत प्रधान राजू का कहना है कि जाहू से भरेड़ी सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनने पर खराब सड़क से हमेशा के लिए निजात मिलेगी।

जूनियर ड्राफ्ट्समैन की परीक्षा का परिणाम घोषित

हमीरपुर। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर ड्राफ्ट्समैन पोस्ट कोड (615) परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में 16 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। 615000056, 615000087, 615000138, 615000207, 615000266, 615000275, 615000286, 615000307, 615000317, 615000337, 615000362, 615000441, 615000555, 615000586, 615000607, 615000610

पक्षियों पर किताब प्रकाशित करेगा वन्य जीव विभाग

वेटलैंड पोंग में आने वाले विदेशी पक्षियों के बारे में मिलेगी जानकारी

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। हमीरपुर

पक्षी प्रेमी अब पोंग क्षेत्र में आने वाले मेहमान पक्षियों के बारे में जान सकेंगे। विदेशी पक्षियों के बारे में वन्य जीव विभाग किताब प्रकाशित करेगा। पोंग क्षेत्र में आने वाले विदेशी पक्षियों के बारे में इस किताब के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। वन्य जीव विभाग ने किताब प्रकाशन के लिए कार्य शुरू कर दिया है। इस किताब में पक्षियों की संख्या, उनके खाने-पीने और

रहने आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। पोंग क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को वन्य जीव विभाग यह किताब उपलब्ध करवाई जाएगी



पोंग में आने वाले पर्यटकों की दी जाएगी किताबें

उन लोगों के लिए यह किताब काफी लाभदायक होगी। इसके साथ ही पक्षियों के संरक्षण में भी

ताकि, कर्मचारियों को भी इन पक्षियों के बारे में जानकारी हो। इस किताब में यह भी बताया जाएगा कि पूरे विश्व में इनकी क्या स्थिति है। जो लोग वन्य जीवों से लगाव रखते हैं, उन लोगों के लिए यह किताब काफी लाभदायक होगी। इसके साथ ही पक्षियों के संरक्षण में भी

इससे लाभ होगा और लोगों को पक्षियों के प्रति रुझान बढ़ेगा। इस संबंध में वन्य प्राणी मंडल हमीरपुर के डीएफओ कृष्ण कुमार का कहना है विदेशी पक्षियों पर किताब छपने का कार्य चला हुआ है। कुछ ही दिनों में इस किताब को लांच किया जाएगा। इस किताब में पक्षियों की विश्व में कितनी संख्या है, वर्तमान में इसकी संख्या घट रही है या बढ़ रही है और इनकी संख्या कम होने का क्या कारण है आदि के बारे में बताया जाएगा।

पंचायत प्रतिनिधियों को दी 'जनमंच' की जानकारी

रमित शर्मा। भोरंज

भरेड़ी में पांच अगस्त को आयोजित होने वाले जनमंच कार्यक्रम तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सोमवार को स्वयं सहायता समूहों तथा पंचायत प्रतिनिधियों को जागरूक किया गया। वहीं,

चयनित पंचायतों में चला स्वच्छता अभियान

बीडीओ ने कहा कि जनमंच के तहत चयनित पंचायतों में स्वच्छता अभियान के साथ पारंपरिक पेयजल स्रोतों की भी सफाई की जा रही है, जबकि मनरेगा के तहत चल रहे विकास

कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बीडीओ ने ली बैठक

कार्यों का निरीक्षण भी किया गया है। उन्होंने सभी पंचायत सचिवों को निर्देश दिए कि जनमंच के बारे में आम लोगों तक जानकारी पहुंचाएं तथा लोगों के आवेदनों को तुरंत ई-समाधान भी अपलोड करें। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही निशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया जाएगा।

भोरंज की पपलाह, ककड़, धर्मरोल, लुदर महादेव, हणोग, धनेड, अमरोह, करसाड़, जाहू, भोरंज, टिकरी मिहल्ला जबकि बमसन की बधानी, बजडोह, चंबोह, कंज्याण, कोट लंगासा पंचायतें शामिल की गई हैं।



जनमंच कार्यक्रम के लिए चयनित गांव की सफाई-सफाई करते लोग।

बरसात ने बिगाड़ी बड़सर की सड़कों की सूरत

बड़सर। बरसात में सड़कों की बदहाली ने विभाग की कार्यप्रणाली की पोल खोल कर रख दी है। बिजड़-भोटा वाया रोपड़ी सड़क मार्ग जानलेवा साबित होने लगा है। खड्ड का रूप धारण कर चुके मार्ग पर सफर करना खतरों से खाली नहीं है। मार्ग जगह-जगह से उखड़ चुके हैं। कई जगह लहसै गिरने से मार्ग पर पथर व कीचड़ आ गया है। इस कारण वाहन चालकों को दिकत का सामना करना पड़ रहा है। पपलोहल के समीप शुक्र खड्ड में पानी का बहाव तेज होने से छोटे वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। सड़क के किनारे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण बारिश का साग पानी सड़क पर एकत्रित हो रहा है। ऐसे में लोगों को पैदल चलने में भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उपर, सहायक अभियंता अनिल कुमार ने कहा कि कई ऐसे संपर्क मार्ग, जिनमें समस्याएँ हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय लेवर की कमी के चलते समस्या पैदा हो रही है। मौसम साफ होते ही खराब चल रही सड़कों की दशा सुधार दी जाएगी।

अवाहदेवी में उड़ रही स्वच्छता अभियान की ध्वजियां

अवाहदेवी। एक तरफ जहां देश और प्रदेश को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं हमीरपुर और मंडी दो जिलों की कुलदेवी अवाहदेवी कस्बे में इस अभियान की ध्वजियां उड़ाने जा रही हैं। यहां शौचालय की व्यवस्था न होने से दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालु खुलेआम शौच जाने पर मजबूर हैं। हालांकि वर्ष 2005 में यहां एक अदद शौचालय का निर्माण किया गया था। जिस पर प्रशासन ने 4.50 लाख खर्च किए थे। तत्कालीन बाजार सुधार सभा ने कस्बे के व्यवसायियों से शौचालय व बाजार की सफाई-सफाई व रख-रखाव के लिए मासिक चंदा तय किया था जो करीब एक साल तक चलता रहा। बाद में 70 फीसदी व्यवसायियों ने चंदा देने से मना कर दिया। नतीजतन सफाई न होने की वजह से अब यह पूर्णतः उखड़ में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ झाड़ियां आ गई हैं। छत व दीवारों पर सीलन आने से दरारें आ चुकी हैं। बगवाडू पंचायत जिसके तहत शौचालय पड़ता है ने भी इसके सिरे पर एक पट्टिका टेंक रखी है। जिस पर लिखा है शौचालय की मरम्मत का कार्य चल रहा है। इसका इस्तेमाल न करें।

उपभोक्ताओं को लूट रहा विद्युत विभाग : प्रदीप

दिन में 8 घंटे बिजली बंद रखी जाती है। जब विद्युत विभाग उपभोक्ताओं को संतोषजनक सेवाएँ ही नहीं दे पा रहा है तो सर्विस चार्ज में इजाफा किस बात का। विभाग के पास न तो पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी हैं और न ही उपकरण उपलब्ध रहते हैं। अगर किसी के घर की बिजली की सप्लाई में फॉल्ट आता है तो उसे ठीक करने के लिए विद्युत कर्मचारी ही नहीं मिलता है। विद्युत विभाग अव्यवस्थाओं की पोटली बना है तथा इस पोटली से नित नई परेशानियाँ निकल रही हैं।

विद्युत बिलों में सर्विस चार्ज में 10 रुपये की बढ़ोतरी की कांग्रेस ने निंदा की है तथा सर्विस चार्ज को तुरंत वापस लेने की मांग की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नादौन ब्लॉक कांग्रेस के प्रवक्ता एडवोकेट प्रदीप रतन ने कहा कि विद्युत विभाग की सेवाएँ बढ़हाल हैं और ऐसे सर्विस चार्ज बढ़ाना उपभोक्ताओं के साथ मजाक है तथा उनसे एक प्रकार की जबरन वसूली है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे लगभग कोई 10 बार बिजली चली जाती है। महीने के एक

लेटलतीफी दो साल से शिमला में धूल फांक रही हमीरपुर रोजगार कार्यालय भवन की फाइल

जमीन-बजट मंजूर, पर फिर भी शुरु नहीं हुआ निर्माण

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। हमीरपुर

रोजगार विभाग हमीरपुर में दो साल से मंजूर जमीन में अपने भवन का निर्माण शुरू नहीं कर पाया है। इसके लिए करीब पौने दो करोड़ का बजट भी मंजूर हो गया है। यहां बनने वाले आलीशान भवन को मॉडल करियर गाइडेंस सेंटर का नाम भी दिया जाना था। इसमें बेरोजगारों को कॉर्सेसिलिंग के साथ रोजगार कार्यालय, श्रम निरीक्षण कार्यालय सहित कामगार कल्याण बोर्ड का कार्यालय भी स्थापित होना था, लेकिन अभी तक इसका निर्माण शुरू होना तो दूर की बात, टेंडर प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है। शिमला से पूरी होने वाले

औपचारिकताओं के बारे में जिला रोजगार अधिकारी तक अनजान हैं। उधर, जिला के बेरोजगार युवा हमीरपुर में मिलने वाली इस नई सुविधा के इंतजार में बैठे हैं। बता दें कि हमीरपुर में करीब तीन दशक से एक तंग हाल किराए के भवन में जिला रोजगार कार्यालय, लेबर इम्प्लेक्ट का कार्यालय और करीब 4 साल से पंजीकृत मजदूरों को सुविधाएँ मुहैया

करवाने के लिए कामगार कल्याण बोर्ड का कार्यालय चल रहा है। इसमें कर्मचारियों और बेटे के लिए सही स्पेस नहीं, ऊपर से हर साल बढ़ता रिकॉर्ड उनकी परेशानी अलग से बढ़ रहा है। नई आधुनिक सुविधाओं को अलग से स्थापित करवाना यहां डेरी खीर बना हुआ है। सैकड़ों लोगों को इन कार्यालयों में आना-जाना लगा रहता है। उनके

एक तंग गैलरी में खड़े होकर अपने सारे काम निपटाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दशकों से इस भवन में रोजगार कार्यालय का कब्जा होने के चलते अब मकान मालिक भी इसे खाली करवाने के लिए तैयार हो गया है। उसने करीब दो साल पहले नोटिस देकर इसे खाली करवाने का अपना इरादा जाहिर कर दिया था। लेकिन विभाग ने उनसे गुहार लगाकर अलग से सही जगह मिलने तक और अपनी विलिडेंस तैयार होने तक यहां पहले की तरह किराए पर काम जारी रखने की गुहार लगाई थी। उसके बाद थोड़ा मामला शांत हुआ था। लेकिन विभाग ने अपनी

भवन निर्माण को करीब एक कनाल जमीन बाईपास के साथ मंजूर हो चुकी है। करीब पौने दो करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर है। पीडब्ल्यूडी को निर्माण एजेंसी बनाया गया। इसके लिए सारी औपचारिकताएँ शिमला से पूरी होनी हैं। -योगराज धीमान, जिला रोजगार अधिकारी

बिल्डिंग का मामला इसी तरह उठे बस्ते में डाले रखा तो इसे खाली करवाने का मामला फिर से सुलगा सकता है।